29 जुलाई, 2016

असफल सैन्य तख्तापलट के बाद तुर्की

*डॉ. ओमेरअनस**

15 जुलाई 2016 को विफल सैन्य तख्तापलट तुर्की की असफल शून्य समस्या नीति की लंबी सूची में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बन गया है। तख्तापलट की नाकाम कोशिश का तत्काल संदिग्ध फ़ेतुल्लाह गुले न और उसका आंदोलन है, जिसके साथ एकेपी सरकार के 2013 से ही संघर्षपूर्ण संबंध रहे हैं। घरेलू स्तर पर, गुलेन तत्वों और अन्य आतंकवादी समूहों को तंत्र से 'साफ' करने के लिए तुर्की को आपातकालीन कानूनों के तहत रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर , तुर्की के अपने नाटो सहयोगियों के साथ, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध दबाव में हैं, क्योंकि तुर्की के राजनीतिक नेतृत्व मानते हैं कि तख्तापलट के प्रयास के पीछे अमेरिकी हाथ है , हालाँकि इस आरोप से अमेरिकी अधिकारियों ने सख्ती से इनकार किया है। दोनों देशों के बीच तनाव ने बहिष्कृत पड़ोसियों और दोस्तों रूस, इज़राइल, ईरान और सीरिया के साथ तुर्की के संबंधों के सामान्य हो जाने को तर्कसंगत बना दिया है।

तख्तापलट की नाटकीय कोशिश ने 1960, 1971, 1980 और 1997 के उत्तर आधुनिक तख्तापलट, जैसे सफल तख्तापलटों की तुलना में पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाया था, तख्तापलट का सबसे नरम रूप जिसमें सेना सत्ता संभालने से पहले ही रुक गयी थी। 15 जुलाई 2016 की रात को जो हुआ वह तख्तापलट से कहीं अधिक था, यह दो अलग-अलग शहरों में फैला हुआ था ; इसने अभूतपूर्व बल जुटाया था जिसमें तीनों सेनाओं के सैनिक शामिल थे। तुर्की के सशस्त्र बलों ने यह पुष्टि करते हुए एक बयान दिया कि तख्तापलट के प्रयास में 35 विमान जिसमें 24 लड़ाकू जेट

विमान और 37 हेलीकॉप्टर शामिल थे, 37 टैंकों और 246 बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल किया गया था।[1] तख्तापलट का विरोध कर रहे कम से कम 246 प्रदर्शनकारियों को तख्तापलट सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। प्रयास की गंभीरता को देखते हुए , अंकारा में अमेरिकी दूतावास ने घटनाक्रम का विवरण देते हुए विवादास्पद शब्द 'विद्रोह' का इस्तेमाल किया था, हालांकि प्रयास विफल होने के बाद इसे हटा दिया गया था।[2]

प्रयास तब विफल होना शुरू हो गया जब यह सार्वजनिक और निजी प्रसारण केंद्रों को तुरंत नियंत्रित नहीं कर सका , जिससे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को मौका मिल गया और उन्होंने सोशल मीडिया और प्रसारण मीडिया का उपयोग कर अपने समर्थकों से तख्तापलट के प्रयास का विरोध करने का आह्वान किया। सत्तारूढ़ दल के लिए यह राहत की बात थी कि चीफ ऑफ स्टाफ हुलुसीकर ने तख्तापलट करने वालों का समर्थन नहीं किया था और वे आगे भी उन्हें सहयोग नहीं कर सकें, इसके लिए उन्हें बंधक बना लिया गया था। इसके अलावा , पिछले तख्तापलटो की तरह , राष्ट्रपति रेसेप तईप ए र्दोगन और प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम दोनों को तुरंत हिरासत में नहीं लिया जा सका। तड़के 3 बजे, राष्ट्रपति एर्दोगन अपने हॉलिडे रिसोर्ट मारमारिस से इस्तांबुल पहुंचे और अपने समर्थकों की प्रचंड भीड़ के बीच उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और तख्तापलट की साजिश रचने वालों और उनके समर्थकों को भयानक परिणाम भुगतने की चेतावनी दी । तख्तापलट के पीछे का प्रमुख संदिग्ध अमेरिकी तुर्की पादरी फेथुल्ला गुलेन और उसका हिज्मेत आंदोलन पहले से ही उनके पास था।

इस्तांबुल में बोस्फोरस ब्रिज, अंकारा और इस्तांबुल में हवाई अड्डा परिसर में अराजक स्थिति थी जहां तख्तापलट विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सैन्य टैंकों की आवाजाही को प्रभावी ढंग से रोक दिया था। इसी तरह , राज्य प्रसारण केंद्र टीआरटी का नियंत्रण वापस लेने के लिए पुलिस हरकत में आ गई। सुबह 6 बजे तक, सरकार ने घोषणा कर दी कि तख्तापलट के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया है, हालांकि दूसरे दिन तक छोटे ऑपरेशन जारी रहे।

तख्तापलट की कोशिश के पीछे कौन है?

तख्तापलट करने वालों के इस सार्वजनिक बयान के बावजूद कि वे देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान की रक्षा करना चाहते थे , एर्दोगन और उनकी सरकार यह मान चुकी थी कि इस प्रयास के पीछे केमलीवादी का हाथ नहीं था , बल्कि यह उनके पुराने सहयोगी फेतुल्लाह गुलेन और उसके हिज्मेत आंदोलन की साजिश थी। यही सोच सत्तारूढ़ एकेपी, मुख्य विपक्षी सीएचपी और राष्ट्रवादी एमएचपी दलों की भी थी। कुर्दिश एचडी पार्टी का अपने धार्मिक विचारों के कारण गुलेन के साथ हमेशा से कड़वा रिश्ता रहा था। पिछले डेढ़ दशक में, सत्तारूढ़ इस्लामिक पार्टी द्वारा मुख्य केमलीवादी ताकतों को राज्य के संस्थानों और राजनीति दोनों से , प्रभावी रूप से दरकिनार कर दिया गया है। 2001 से

2008 तक के संवैधानिक संशोधनों ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एमजीके) के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जो कभी सैन्य शक्ति का केंद्र था और जिसे सरकार का प्रतिभार माना जाता था। चूँकि एर्दोगन ने नेकमेत्तिन एर्बेकन के नेतृत्व वाली मुख्य इस्लामिक रिफाह पार्टी से अलग होने के बाद 2002 में अपनी पार्टी बनाई थी, इसलिए एके पार्टी ने बड़ी संख्या में मौजूद रूढ़िवादी मतदाताओं और सरकार में शामिल अधिकारियों के समर्थन के लिए फेतुल्लाह गुलेन और उसके आध्यात्मिक आंदोलन पर भरोसा किया था।

कई विपक्षी दल एर्दोगन पर गुलेनवादियों को शरण देने और उन्हें अवसर प्रदान करने का आरोप लगाते रहे थे।[3] एर्दोगन और हिज्मेत आन्दोलन के बीच दशकों से चले आ रहे संबंध में 2012 में दरार पड़नी शुरू हुई जब एर्दोगन को आशंका हुई कि गुलेन आन्दोलन समानांतर राज्य स्थापित कर रहा है, एक डीप स्टेट, जिसे अब सिर्फ गुलेन आन्दोलन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है।

फेतुल्लाह गुलेन, हनफ़ी-सुन्नी इस्लाम की एक धार्मिक शाखा का प्रतिनिधित्व करता है , जो मसीहा के इस्लामी स्वरूप महदी के अवतार में विश्वास करता है , जिसके पास मानवता की सभी समस्याओं को दुरुस्त करने का असाधारण कौशल है। गुलेन के कई अनुयायियों का मानना है कि गुलेन स्वयं एक मसीहा है। चूंकि तुर्की का धर्मनिरपेक्ष संविधान निजी मस्जिदों की अनुमति नहीं देता है, इसलिए गुलेन ने 1960 के दशक में प्रेसीडेंसी ऑफ रिलीजियस अफेयर्स (डीआईबी) के तहत एक धार्मिक उपदेशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। जैसे- जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई , धर्मनिरपेक्ष सैन्य नेतृत्व के साथ उसका संबंध बिगड़ता गया और राजनीतिक नेतृत्व उसकी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करने लगा।

सितंबर 2000 में, सेनाध्यक्ष जनरल हुसैन किव्रिकोग्लू ने प्रधानमंत्री बुलेंट एसेविट की गुलेन गतिविधियों के सार्वजनिक समर्थन को अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया, और आरोप लगाया कि "वे [गुलेन अनुयायी] हर दिन राज्य के खिलाफ काम कर रहे थे ताकि इसे उखाड़ फेंक सकें।" उन्होंने आशंका जताई कि वे हर जगह फैल गए थे। [4] 2002 में एके पार्टी के आने से गुलेन आंदोलन को सरकार में अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक नया अवसर मिल गया और इसने अविश्वास बढ़ने से पहले तक धीरे-धीरे अपने शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया साम्राज्य के बड़े नेटवर्क का प्रसार कर लिया।

2007 से 2012 तक, तुर्की के आतंकवाद-रोधी अधिकारियों ने एकेपी सरकार के खिलाफ दो तख्तापलट का पता लगाने का दावा किया था जिसमें दर्जनों वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों , न्यायाधीशों, पत्रकारों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उनपर मुकदमा चलाया गया था। एर्गनेकॉन ट्रायल और स्लेजहैमर के नाम से जाने जाने वाले मामलों में इस्लामिक सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ की गतिविधियों और तख्तापलट की योजनाओं से जुड़ी सबसे संवेदनशील और विस्तृत जानकारी सामने आई है। 2012 में, जांच की सुई नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन

(एमआईटी) के प्रमुख, एर्दोगन के करीबी विश्वासपात्र हकन फिदान तक पहुंच गई और कुर्दिश आतंकी संगठन पीकेके के साथ संबंध को लेकर उनसे अंकारा की आतंकवाद रोधी यूनिट द्वारा पूछताछ की गयी। 2002 में एर्दोगन के सत्ता संभालने के बाद से गुलेन-एर्दोगन के संबंधों में यह पहला बड़ा तनाव था। अन्य आरोपियों में एक खोजी पत्रकार अहमतसिक थे जो पुलिस बल में गुलेन आंदोलन की घुसपैठ पर एक किताब[5] प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे थे।[6]

2013 के अंत तक, एर्दोगन सरकार को यह विश्वास हो गया था कि गुलेन आंदोलन के प्रति निष्ठावान अधिकारी अपने प्रभावशाली पदों का उपयोग कर एक समानांतर राज्य का निर्माण करने के लिए दोनों मामलों में फर्जी दस्तावेजों को तैयार करके संकट पैदा कर सकते हैं। इस बीच , अवैध रूप से फोन टैपिंग और भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे जिसके लिए एर्दोगन ने गुलेन तत्वों को घेरे में लिया।[7] अगस्त 2015 में, जब अदालत के फैसले के बाद एर्गेनकोन मामले में कई आरोपी अधिकारियों को बरी कर दिया गया, तो उसके तुरंत बाद मुख्य उत्पीड़नकर्ता ज़ेकेरियाज़ अन्य मामलों में गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए आर्मेनिया भागने में कामयाब रहा। [8] ज़ेकेरियाज़ को गुलेन का करीबी सहयोगी माना जाता था। [9] सत्तारूढ़ और विपक्षी दल दोनों इस बात पर सहमत थे कि दोनों साजिश के पीछे गुलेन तत्वों का हाथ है।[10] गुलेन तत्वों के खिलाफ विरोधियों की आलोचना तब सही साबित हो गयी जब 2012 में एर्गनेकॉन ट्रायल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी संख्या में आरोपियों को बरी कर दिया।[11]

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

अधिकतर देशों ने तख्तापलट के प्रयास को जल्दी ही खारिज कर दिया और निर्वाचित सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया लेकिन तुर्की के महत्वपूर्ण सहयोगियों की कुछ प्रतिक्रियाओं ने एक अलग ही संदेश दिया। पहली अमेरिकी प्रतिक्रिया तख्तापलट के प्रयास के शुरुआती घंटों में विदेश सचिव जॉन केरी की ओर से मास्को से आई जिसमें उन्होंने तुर्की में "शांति, स्थिरता और निरंतरता" की आशा व्यक्त की, लेकिन यह प्रतिक्रिया पर्याप्त स्पष्ट नहीं थी। अपने अमेरिकी समकक्ष जॉन केरी के साथ उसी मीडिया वार्ता के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वहां की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होने का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया ।[12] देर रात राष्ट्रपति ओबामा की सचिव जॉन केरी के साथ हुई बातचीत के बाद कहा गया “राष्ट्रपति और सचिव दोनों इस बात पर सहमत हैं कि तुर्की में सभी दलों को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का समर्थन करना चाहिए”, एक स्पष्टता जो केरी की रूसी राजधानी से की गई प्रारंभि क प्रतिक्रिया में नहीं थी।[13]

अगले दो दिनों में, तुर्की मीडिया और राजनेताओं ने तख्तापलट के पीछे अमेरिकी हाथ होने की व्यापक रूप से आलोचना की और अमेरिका से फ़ेतुल्ला गुलेन के प्रत्यर्पण की अपनी मांग को तेज कर दिया। 17 जुलाई को एर्दोगन-पुतिन की टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद , ओबामा ने 19

जुलाई को एर्दोगन को फोन किया जिसमें उन्होंने "उचित सहायता प्रदान करने" की अपने प्रशासन की इच्छा जताई।[14] लेकिन इस बीच एक बार फि र विदेश सचिव जॉ न केरी की ओर से विवादास्पद बयान आया जिसमें वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार कहा गया था कि तुर्की की नाटो सदस्यता ख़तरे में पड़ सकती है, हालांकि अंकारा में अमेरिकी दूतावास द्वारा तुरंत इसका खंडन कर दिया गया।[15] तुर्की के राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के तीखे बयानों ने अमेरिका पर "आतंकवादी" गुलेन को शरण देने के आरोपों को हवा दी।[16]

तुर्की के पश्चिमी आलोचकों के लिए, तुर्की नाटो और अमेरिका के लिए एक दायित्व बन गया है।[17] तुर्की को लेकर पश्चिम का धैर्य पहले ही अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था क्योंकि एक अमेरिकी उद्यम, एक महत्वपूर्ण अमेरिकी थिंक टैंक, ने मार्च 2016 में एर्दोगन सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सैन्य तख्तापलट की आशंका जताई थी। [18] तुर्की को उसकी तत्काल सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर अलग-थलग छोड़ दिया गया है; सीरियाई गृहयुद्ध, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ गठबंधन, कुर्द आतंकवाद और यूरोप में शरणार्थी संकट।

यह सब ऐसे समय में हुआ है जब तुर्की लंबे समय तक सीरियाई संकट के बाद अपनी विदेश नीति को फिर से संगठित करने की प्रक्रिया में है। मई 2016 में अहमत दवुतोग्लू के एके पार्टी की निर्णय लेने वाली प्रमुख केंद्रीय समिति में समर्थन खो देने के बाद प्रधानमंत्री बीनाली यिल्दिरिम के नेतृत्व में नई सरकार आई। थोड़े समय के भीतर, बीनाली यिल्दिरिम ने इजरायल और रूस के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं ताकि तुर्की के "दोस्तों के घेरे" का विस्तार किया जा सके, और उनके फैसले को तर्कसंगत बनाने के लिए इस नामकरण का इस्तेमाल किया गया।[19] यही कारण है कि रू सी और ईरानी दोनों ही अधिकारी गुलेन समर्थक मीडिया, नागरिक अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों को लेकर तुर्की के तख्तापलट बाद की 'सफाई अभियान' की आलोचना करने से बचते हैं।

गुलेन विरोधी अभियान

तुर्की के नाटो सहयोगियों के लिए, तख्तापलट के बाद चलने वाला सफाई अभियान एक और ज्वलंत बिंदु बन गया है क्योंकि उनके बयानों में उन्होंने तुर्की से "लोकतंत्र, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने" की मांग की है।[20] मृत्युदंड को वापस लाने के एर्दोगन के प्रस्ताव ने यूरोपीय संघ को यह कहने के लिए मजबूर किया है कि ऐसा कदम तुर्की के लिए यूरोपीय संघ के दरवाजे बंद कर देगा। हुर्रियत डेली न्यूज के अनुसार, तुर्की सरकार ने 15 जुलाई 2016 से अब तक कुल 8,777 अधिकारियों को ड्यूटी से निलंबित किया है।[21] कम से कम 42 पत्रकारों पर तख्तापलट के प्रयास का समर्थन करने का आरोप लगा कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। डेली सबह के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील्स के कम से कम 100 जजों और काउंसिल ऑफ स्टेट के 34 सदस्य, जो कि एक और उच्चस्तरीय न्यायिक प्राधिकरण है और निचली अदालतों के

सैकड़ों जजों के साथ-साथ अब तक 737 अभियोजकों को हिरासत में लिया गया है। सेना से 143 जनरलों को गिरफ्तार किया गया है और निचली रैंक के 3,168 सैन्य अधिकारियों और 736 सैन्य कैडेटों को भी गिरफ्तार किया गया है। करीब 918 पुलिस अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया, जबकि राज्यपालों सहित 825 सार्वजनिक अधिकारी गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थे।[22] तख्तापलट विरोधी अभियान के मुख्य शिकार होने वालों में मीडिया पेशेवर, मानव अधिकार कार्यकर्ता और गुलेन एवं उनके आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग शामिल हैं। अब तक 130 मीडिया को बंद कर दिया गया है जिन में 3 समाचार एजेंसियां, 16 टीवी चैनल, 23 रेडियो स्टेशन, 45 समाचार पत्र, 15 पत्रिकाएं और 29 प्रकाशन गृह हैं, जिन पर गुलेन आंदोलन से जुड़े होने का आरोप है।[23]

तुर्की की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति ने एर्दोगन को कार्यकारी राष्ट्रपति पद पर नहीं रहते हुए भी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की है। एर्दोगन द्वारा आपातकालीन कानूनों के माध्यम से इस तख्तापलट के बहाने अपने हाथों में अधिक शक्ति केंद्रित करने के बाद तुर्की के सामने राजनीतिक ध्रुवीकरण के और बड़े खतरे मंडरा रहे हैं।

राजनीतिक संकट और अधिक आर्थिक संकट के साथ जुड़ा होता है क्योंकि असफल तख्तापलट के प्रयासों से निवेशकों का विश्वास हिल गया है और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एसएंडपी) ने अन्य एजेंसियों के मुकाबले तुर्की की क्रेडिट रेटिंग में कटौती कर दी है।[24]

सीरियाई सीमा के पास रूसी जेट पर हमले के बाद, रूसी पर्यटकों को रोक दिया गया था और रूस में सब्जियों को ले जाने वाले तुर्की ट्रकों को अनिश्चितकाल तक रोके रखा गया था, जिसके बाद रूसी सरकार ने कई कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। 2015-2016 में तुर्की अर्थव्यवस्था की वार्षिक विकास दर 3.5 प्रतिशत तक कम हो गयी थी।[25] ब्लूमबर्ग ने रूसी संघीय सीमा शुल्क सेवा के हवाले से कहा कि 2016 के पहले पांच महीनों में रूस और तुर्की के बीच व्यापार एक साल पहले की तुलना में 57.2 प्रतिशत घटकर 6.1 बिलियन डॉलर हो गया।[26] बाजार पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि तुर्की में सत्तावादी शासन की मौजूदगी निवेशकों के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। तुर्की की अर्थव्यवस्था "किसी ऐसे देश के प्रति निवेशकों की भावनाओं में अचानक बदलाव के प्रति संवेदनशील" है जो लंबे समय से घाटे में है।"[27]

एकेपी सरकार द्वारा एक सफल जनांदोलन के जरिये तख्तापलट के प्रयास को विफल कर देने के बाद एर्दोगन और उनकी पार्टी की लोकप्रियता फिलहाल बढ़ रही है। एकेपी और उसके विरोधी दोनों ही सफलता में अपना हिस्सा होने का दावा कर रहे हैं और इस कारण उत्साह का एक अस्थायी भाव मौजूद है और सभी पक्षों के बीच एक साझा आधार की तलाश की जा रही है। राष्ट्रपति एर्दोगन और विपक्षी नेताओं के बीच हाल की बैठकों को पारस्परिक रूप से लाभप्रद देखा जा सकता है। लेकिन मौजूदा सफाई अभियान जल्द ही एर्दोगन और विपक्षी दलों के बीच फिर एक विभाजन रेखा बना

देगा। तख्तापलट की असफल कोशिश राष्ट्रपति एर्दोगन के लिए एक मौ का है कि वे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्र एवं पश्चिमी सहयोगियों के बीच तुर्की के घटते आर्थिक और राजनीतिक दबदबे में से किसी एक का चयन करें। यह देखा जाना शेष है कि वे किस मार्ग का चयन करते हैं।

तुर्की के अधिकांश पश्चिमी सहयोगियों द्वारा जिस तथ्य की अनदेखी की जा रही है, वो यह है कि फ़ेतुल्ला ह गुलेन और उसके हिज्मेत आंदोलन ने तुर्की के ध्रुवीकृत राजनीतिक परिदृश्य में अपने अधिकांश समर्थकों को खो दिया है। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री बुलेंट एस्विट ने गुलेन को सेना के प्रमुख जनरल हुसैन किव्रीकोग्लू से बचाया था, जिन्होंने व्यवस्था में घुसपैठ के लिए हमेशा गुलेन आंदोलन की सार्वजनिक रूप से निंदा की थी।[28] 2002 से 2012 तक, एक धार्मिक रूढ़िवादी पार्टी के रूप में एकेपी गुलेन आंदोलन की स्वाभा विक सहयोगी थी और इसने गुलेन आंदोलन के साथ शालीनता बरतने के कई आरोपों का सामना किया था। वर्तमान समय में , तुर्की के राजनीतिक परिदृश्य में गुलेन आंदोलन को अपने समर्थन के लिए कोई जगह नहीं बची है।

जिस तरह से तुर्की की राजनीतिक पार्टियाँ फ़ेतुल्लाह गुलेन को प्रत्यर्पित करने की अमेरिकी सरकार से माँग कर रही हैं, उसने एक नई राजनीतिक गाथा तैयार कर दी है जहाँ गुलेन का बचाव करना और एर्दोगन की आलोचना करना केवल एर्दोगन के घरेलू एजेंडे को ही मजबूत करेगा। इस पृष्ठभूमि में, अपनी असफल विदेश नीति को पुनर्स्थापित करने के एर्दोगन के प्रयास को यूरोप की उपलब्धियों को खोए बिना अपने करीबी पड़ोसियों रूस, ईरान, सीरिया और इराक के बीच अधिक दोस्तों की तलाश करने के तौर पर देखा जाता है।

निष्कर्ष

अल्पावधि में, असुरक्षा की चरम भावना, बाद के हमलों यानी तख्तापलट के अन्य प्रयासों के डर को गुलेन से संबद्ध व्यक्तियों और संस्थानों पर आपातकाल की स्थिति और ब्लैंकेट क्रैकडाउन की घोषणा के पीछे के मुख्य कारण के रूप में पेश किया जाता है। इस घोषणापत्र का सीएचपी और एचडीपी द्वारा विरोध किया गया था , लेकिन इसे गंभीरता से चु नौती नहीं दी गई क्योंकि इसे तुर्की के राष्ट्रवादी नागरिक समाज और एमएचपी जैसे राजनीतिक समूह से मजबूत स मर्थन प्राप्त था। आपातकालीन कानूनों के तहत अगले तीन महीनों के लिए , सरकार पूरे तन्त्र को गुलेनवादियों से मुक्त कराने के अपने एजेंडे पर केंद्रित रहेगी, जिसमें एर्दोगन और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए कई चुनौतियां आ सकती हैं।

गुलेनविरोधी ऑपरेशन जितना लंबा होगा, राजनीतिक रूप से यह उतना ही भारी पड़ेगा । एकेपी सरकार गुलेन आंदोलन को बंद कर सकती है या नहीं, यह पूरी तरह से उन लोगों से बात करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, जिन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए

गुलेन का अनुसरण किया था। चूंकि गुले न समर्थकों के साथ बातचीत के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है, उनकी आध्यात्मिक और बौद्धिक उपस्थिति एर्दोगन और उनकी सरकार के अनुमान से अधिक समय तक रहेगी। सार्वजनिक कार्यालयों से अधिक सामूहिक गिरफ्तारी या निलंबन से देश में केवल राजनीतिक अशांति गहरा सकती है क्योंकि प्रभावित परिवारों के सदस्यों को इस ऑपरेशन के कारण खोई हुई आय और गरिमा का एक वैकल्पिक स्रोत खोजना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर , तुर्की के अपने पश्चिमी सहयोगियों के साथ कई मुद्दों पर गंभीर आलोचना हो रही है। सीरिया में कुर्द समूह पीवाईडी के साथ अमेरिका का सहयोग, फेतुल्लाह गुलेन को आश्रय और लंबे समय तक सीरिया के संकट ने तुर्की के सत्तारूढ़ व्यवस्था को निराश किया है। तख्तापलट के प्रयास को लेकर पश्चिमी प्रतिक्रिया केवल असंतोष को बढ़ा सकती है। इस संदर्भ में, रूस, ईरान और इजरायल के साथ संबंधों में बदलाव करके नाटो से परे सोचने के लिए एक नई विदेश नीति उभर सकती है, खासकर जब ऐसी नीति तुर्की को उसके आर्थिक संकटों को तत्काल राहत दे सकती है।

यह देखते हुए कि तुर्की ने सीरियाई-इराक़ी सीमा संकट पर पहले ही अपने संसाधनों और ऊर्जा को झोंक दिया है, और यथास्थिति को बनाए रखने के लिए तुर्की के पास पर्याप्त आंतरिक या बाहरी समर्थन नहीं है , उभरता हुआ पुनर्वितरण सबसे अधिक अपेक्षित था और शायद एकमात्र विकल्प। इसका अर्थ है कि सीरिया के गृहयुद्ध , कुर्दिश उग्रवाद और इस्लामिक स्टेट के लिए युद्ध पर आने वाले महीनों में एक और निर्णायक तुर्की प्रति क्रिया होगी। यदि ऐसा हुआ तो एर्दोगन की सत्तावादी महत्वाकांक्षाएं इस प्रक्रिया की एकमात्र जोखिम होंगी और एके पार्टी के भीतर शक्ति संघर्ष नए सिरे से शुरू होगा।

***

** डॉ ओमेर अनस भारतीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में रिसर्च फेलो हैं*

अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और परिषद के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

अंत टिप्पण:

1 "Turkish Military Says Coup Plotting Soldiers Account For 1.5 Per Cent Of Its Force", 27 July 2016, http://www.ndtv.com/world-news/turkish-military-says-coup-plotting-soldiers-account-for-1-5-per-cent-of-its-force-1436874

2 "US Embassy in Ankara first called coup 'uprising,' later 'coup'", 18 July 2016, http://www.dailysabah.com/politics/2016/07/18/us-embassy-in-ankara-first-called-coup-uprising-later-coup

3 "Post-coup attempt arrests should not turn into a witch hunt: CHP", 27 July 2016, *Hurriyet Daily News,* http://www.hurriyetdailynews.com/post-coup-attempt-arrests-should-not-turn-into-a-witch-hunt-chp.aspx?pageID=238&nID=102158&NewsCatID=338

[4] The Guardian, 1 September 2000, "Turkey accuses popular Islamist of plot against state", https://www.theguardian.com/world/2000/sep/01/1

[5] Imamın Ordusu, (The Imam's Army) published in 2012

[6] "Analysis: Turkey's divisive Ergenekon trial", 12 August 2013, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/08/201381175743430360.html

[7] "AKP, Gulen community in open war", Al Monitor, 18 November 2013, http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/11/gulen-akp-conflict-prep-schools.html#ixzz4ErMk4JGH

[8] "Turkish prosecutor of corruption, coup cases flees to Armenia over 'coup attempt' arrest warrant", *Hurriyet Daily News,* 10 August 2015, http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-prosecutor-of-corruption-coup-cases-flees-to-armenia-over-coup-attempt-arrest-warrant.aspx?pageID=238&nID=86752&NewsCatID=509

[9] "Turkish appeals court overturns 'Ergenekon' coup plot convictions ", Reuter 21 April 2016, http://www.reuters.com/article/us-turkey-coup-trial-idUSKCN0XI1WS

[10] "Opposition CHP's rally brings Turkish parties together in Istanbul's Taksim Square", 24 July 2016, *Daily Sabah,* http://www.dailysabah.com/politics/2016/07/24/opposition-chps-rally-brings-turkish-parties-together-in-istanbuls-taksim-square

[11] "Coups away", 11 February 2010, *The Economist* http://www.economist.com/node/15505946

[12] Reuter, 15 July 2016, http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-usa-russia-idUSKCN0ZV2NQa

[13] "Readout of the President's Call with Secretary John Kerry", 15 July 2016, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/07/15/readout-presidents-call-secretary-john-kerry

[14] "Readout of the President's Call with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey", 19 July 2016, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/07/19/readout-presidents-call-president-recep-tayyip-erdogan-turkey

[15] https://www.washingtonpost.com/world/kerry-warns-turkey-nato-membership-potentially-at-stake-in-crackdown/2016/07/18/f427ba8a-4850-11e6-8dac-0c6e4accc5b1_story.html
http://www.dailysabah.com/politics/2016/07/18/us-embassy-denies-washington-post-report-on-kerry

[16] Press TV 16 July 2016, US slams Turkey's hint of US involvement in coup http://www.larouchepub.com/eiw/public/1999/eirv26n36-19990910/eirv26n36-19990910_045-the_neo_ottoman_trap_for_turkey.pdf http://www.presstv.ir/Detail/2016/07/16/475523/US-blasts-Turkey-claim-of-US-role-in-coup

[17] "Turkey is now a huge liability for NATO — and America", *The week*, 3 December 2015, http://theweek.com/articles/591808/turkey-now-huge-liability-nato--america

[18] " WILL THERE BE A COUP AGAINST ERDOGAN IN TURKEY?", 3 March 2016, *Newsweek,* http://www.newsweek.com/will-there-be-coup-against-erdogan-turkey-439181

[19] "Turkey hints at normalization of ties with Syria", 13 July 2016, http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/07/13/Turkey-hints-at-normalization-of-ties-with-Syria.html

[20] "Europe and US urge Turkey to respect rule of law after failed coup", 18 July 2016, *The Guardian,* https://www.theguardian.com/world/2016/jul/18/european-leaders-urge-turkey-to-respect-rule-of-law-after-failed-coup

[21] http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-detains-istanbul-governor-academics-after-failed-coup-attempt.aspx?pageID=238&nID=102084&NewsCatID=338

[22] "Number of detained coup plotters, accomplices nears 10,000", 26 July 2016, *Daily Sabah* http://www.dailysabah.com/investigations/2016/07/27/number-of-detained-coup-plotters-accomplices-nears-10000

[23] "1,684 soldiers discharged from Turkish Army ahead of key military council", 27 July 2016, *Hurriyet Daily News,* http://www.hurriyetdailynews.com/1684-soldiers-discharged-from-turkish-army-ahead-of-key-military-council.aspx?PageID=238&NID=102177&NewsCatID=341

[24] "Consultancies critical of 'rushed' S&P Turkey downgrade", 26 July 2016, http://aa.com.tr/en/economy/consultancies-critical-of-rushed-sp-turkey-downgrade/616015

[25] "Turkey's economy after the coup", 23 July 2016, http://www.aljazeera.com/programmes/countingthecost/2016/07/turkey-economy-coup-160723082548100.html

[26] "Putin, Erdogan Mend Ties as Post-Coup Turkey Turns to Russia", 26 July 2016, http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-26/putin-erdogan-mend-ties-as-post-coup-turkey-turns-toward-russia

[27] "Bad Time for Turkey Economy After Attempted Coup", 24 July 2016, http://www.ndtv.com/world-news/bad-time-for-turkey-economy-after-attempted-coup-1435364

[28] The Guardian, 1 September 2000, "Turkey accuses popular Islamist of plot against state", https://www.theguardian.com/world/2000/sep/01/1